

**Fourteenth Loksabha****Session : 6****Date : 16-12-2005****Participants : Rawat Prof. Rasa Singh**

an&gt;

**Title : Need to accord special category status to Rajasthan under A.P.D.R.P Scheme.**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें 60 प्रतिशत रेगिस्तानी/उप रेगिस्तानी क्षेत्र है। कम वार्षिक औसत वार्षिक का अर्थ है कि राज्य में जल संसाधनों की अत्यन्त कमी है जिससे राज्य को अकाल की विभीषिका का निरन्तर सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप सस्ते जल विद्युत उत्पादन के संसाधन भी सीमित हैं तथा तापीय विद्युत उत्पादन की लागत भी तुलनात्मक रूप से अधिक है क्योंकि कोयला क्षेत्र हमसे बहुत दूर हैं। फिर भी ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु विभिन्न उपायों की शुरुआत करने में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य था जिसकी भारत सरकार एवं अन्य संस्थानों द्वारा सराहना भी की गई है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान को पूर्वी राज्यों के समान विशिष्ट राज्य का दर्जा प्रदान करे और त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण परियोजना लागत की 90 प्रतिशत राशि, केन्द्र अनुदान के रूप में दे तथा 10 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में राजस्थान को उपलब्ध कराई जाए।